

सचिाई परियोजनाओं के लिये 9020 करोड रुपए

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के दौरान 9020 करोड रुपए तक के अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने की मंजूरी दी है। यह राशािाष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सचिाई योजना के तहत चल रही प्राथमिकता वाली 99 सचिाई परियोजनाओं और इसके साथ-साथ उनके कमांड क्षेत्र विकास के त्वरति सचिाई लाभ कार्यक्रम कार्यों के कार्यान्वयन के लिये ऋण के संदर्भ में 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर सुनिश्चित करने के लिये ऋणपत्र जारी करके जुटाई जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- त्वरति सचिाई लाभ कार्यक्रमों के तहत अनेक प्रमुख और मध्यम सचिाई परियोजनाएँ मुख्य रूप से नधियों के अपर्याप्त प्रावधानों के कारण अधूरी पड़ी थीं।
- वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सचिाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अधीन चल रही 99 परियोजनाओं को दसिम्बर 2019 तक कई चरणों में पूरी करने के लिये पहचान की गई थी।
- बड़ी मात्रा में नधिाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिये केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी के तहत पहचान की गई मौजूदा परियोजनाओं के लिये 20 हजार करोड रुपए की आरंभिक नधिाई के साथ नाबार्ड में समरपति दीर्घकालीन सचिाई नधिाई (Long Term Irrigation Fund-LTIF) के सृजन की घोषणा की थी।
- राज्यों के लिये नाबार्ड से ऋण को आकर्षक बनाने के लिये वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान नाबार्ड को प्रतिवर्ष अपेक्षति लागत मुक्त नधिाई उपलब्ध कराकर ब्याज की दर 6 प्रतिशत के आस-पास बनाए रखने का निर्णय लिया गया था।
- वर्ष 2016-17 के दौरान नाबार्ड ने एलटीआईएफ के तहत कुल 9086.02 करोड रुपए की राशावितरति की।
- राज्यों और केंद्रीय जल आयोग द्वारा वभिन्नि समीक्षा बैठकों के दौरान बताई गई स्थितिके अनुसार 18 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं या लगभग पूरी होने वाली हैं।
- इन सभी 99 परियोजनाओं से 2016-17 के दौरान 14 लाख हेक्टेयर से अधिक सचिाई की उम्मीद है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान 33 से अधिक परियोजनाओं के पूरी होने की संभावना है। पहचान की गई सचिाई परियोजनाओं के पूरा होने और निर्माण चरण के दौरान बड़ी तादाद में नयिमति रोजगारों के साथ रोजगार के अन्य अवसरों का सृजन होगा।
- यह भी महत्त्वपूर्ण है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 76 लाख हेक्टेयर की सचिाई की संभावना इस क्षेत्र में कृषि परिदृश्य को पूरी तरह बदल देगा, जिसके परिणामस्वरूप फसलों की सघनता, फसल प्रणाली में परिवर्तन, कृषि प्रसंस्करण और अन्य सहायक गतिविधियों के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

नाबार्ड (NABARD) : एक नज़र

- नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये एक शीर्ष बैंक है। इसकी स्थापना शिविरमन समितिकी सफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 में की गई थी।
- इसका कार्य कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के संवर्धन और विकास के लिये ऋण प्रवाह को उपलब्ध करना है।
- इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य संबद्ध आर्थिक क्रियाओं को समर्थन प्रदान कर गाँवों का सतत विकास करना है।